

जीईएम और सीसीआई समझौता

संबंधित मुद्दे- किसानों की सहायता में ई-प्रौद्योगिकी।

चर्चा में क्यों

- सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने ई-मार्केटप्लेस में निष्पक्ष एवं प्रतियोगी वातावरण बनाने के लिए फरवरी, 2019 को समझौता किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा विरोधी गलत परम्पराओं की पहचान के लिए सार्वजनिक खरीद क्षेत्र में दोनों संस्थाओं की कुशलता का इस्तेमाल करना है।

जीईएम(GEM) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद मंच है।

- जीईएम ने प्रामाणिक विक्रेताओं के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया और वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद-बिक्री के लिए एक ई-मार्केटप्लेस का निर्माण किया।
- जीईएम का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना है।
- विशेषताएं -
- यह विभिन्न सरकारी विभागों / संगठनों / सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारत सरकार की एक संवैधानिक संस्था है, जिसकी पूरे भारत में प्रतिस्पर्धा कानून, 2002 लागू करने और प्रतिस्पर्धा को गलत तरीके से प्रभावित करने वाली गतिविधियों को रोकने की जिम्मेदारी है।